'सांख्यिकी दिवस-2010' के शुभारम्भ पर दिनांक 29 जून 2010 को 1030 बजे विज्ञान भवन के कक्ष सं. 5 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

मुझे आज के चतुर्थ सांख्यिकी दिवस के प्रारम्भिक सत्र में भाग लेते हुए बहुत खुशी हो रही है जिसे सांख्यिकी के वैश्विक मान्यताप्राप्त गुरू स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। उदीयमान गणतंत्र में विकास आयोजना के निर्माता के रूप में उन्होंने सांख्यिकीय अध्ययनों के विकास को नीतिगत आयोजना और कार्यान्वयन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में दिशा प्रदान करने का कार्य किया था। वह संस्थाओं के भी बहुत बड़े निर्माता थे जिनके माध्यम से उन्होंने सांख्यिकी के अध्यापन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रथम सांख्यिकीय सलाहकार के रूप में देश में आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने की नींव रखी।

यह उपयुक्त ही है कि हम प्रोफेसर महालनोबिस की स्मृति में सांख्यिकीय दिवस मनाते हैं। इस समारोह में देश की सांख्यिकीय विषय से संबंधित बिरादरी को एक साथ बैठने का अवसर मिलता है और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न होती है। मैं प्रोफेसर आलोक डे को भी बधाई देता हूं जिन्हें प्रोफेसर पी. वी. सुखात्मे के सम्मान में शुरू किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आज से डेढ़ सौ वर्ष से भी अधिक समय पूर्व ब्रिटिश इंडिया के प्रथम सांख्यिकीय विवरण से लेकर आज तक हमने काफी लंबी दूरी तय कर ली है। देश के मानवीय और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली अनेक जटिल भिन्नताओं वाली एक विकासशील एवं विविध अर्थव्यवस्था के रूप में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण के महत्व के साथ-साथ इसके बढ़े हुए

दायरे, समयनिष्ठता और इन आंकड़ों की विश्वसनीयता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह समवर्ती सूची का विषय है और विकेन्द्रीकरण पर जोर देकर यह सांख्यिकीय पद्धति आंकड़ों के संग्रहण और सृजन में केन्द्र और राज्य सरकारों को साथ-साथ लाती है।

केन्द्र सरकार आधिकारिक सांख्यिकीय पद्धति की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया है जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नियंत्रक एवं अधिकारप्राप्त निकाय के रूप में कार्य करना, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक विकसित एवं निर्धारित करना तथा केन्द्र और राज्यों के बीच सांख्यिकीय समन्वय स्थापित करना है। सरकार भी आयोग की विभिन्न सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

देवियो और सज्जनो,

यह भी अत्यंत उपयुक्त है कि सांख्यिकी दिवस 2010 की विषय-वस्तु 'बाल सांख्यिकी' है। विश्व में बच्चों की कुल संख्या का पांचवां हिस्सा भारत में रहता है। देश की लगभग 440 मिलियन जनसंख्या बच्चों की है और यह हमारी आबादी का 42 प्रतिशत है। देश के ये युवा नागरिक संभाव्य जनसांख्यिकीय संसाधन हैं, जो राष्ट्र को आर्थिक प्रगति और मानव विकास के उच्च पथ पर ले जा सकते हैं। तथापि, इस संभावना को साकार करना न तो निश्चित है और न ही यह स्वतः-प्रवृत है।

वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। विश्व में कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक तीसरा बच्चा भारत में रहता है; प्रत्येक दूसरे भारतीय बच्चे का वजन कम है; भारत में चार बच्चों में से तीन रक्त-अल्पता से पीड़ित हैं; और प्रत्येक दूसरे नवजात बच्चे में आयोडीन की कमी के कारण उसकी सीखने की क्षमता घट गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बच्चों के विकास संबंधी कार्य दल ने बच्चों की स्थिति और दशा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चिन्ताओं का उल्लेख किया है:

"मृत्यु तथा बीमारी की उच्च दर, शिक्षा तथा विकास के मामले में बदतर उपलब्धि; सेवाओं तथा अवसरों की सुलभता में दीर्घकालिक असंतुलन; उपेक्षा और सुरक्षा की कमी के उच्च जोखिम; सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में सेवा का खंडित और क्षेत्रीकृत विस्तार, विकास के लाभों का असमान वितरण और निवेश तथा देख-रेख के निम्न स्तर।"

हमारे बच्चों को उनके जीवित रहने, उनका संरक्षण और उनका विकास करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता सर्वविदित है। भारत का संविधान बच्चों को विशेष दर्जा प्रदान करता है क्योंकि ये बच्चे "अपनी अल्पायु" से संबंधित संरक्षण को प्राप्त करने और उससे जुड़े रक्षोपायों की हकदारी संबंधी विशेष उपबंधों के पात्र हैं। हमने अभी हाल ही में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए एक विधान अधिनियमित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संबंधी अभिसमय के प्रति हमारी स्वीकृति हम पर अतिरिक्त बाध्यताएं एवं प्रतिबद्धताएं डाल देती हैं। राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 के तहत बच्चों को 'सर्वोच्च राष्ट्रीय परिसंपत्ति' घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 के अनुसार बच्चा 'एक परिसंपत्ति और मानव अधिकारों का पात्र व्यक्ति' है।

इस प्रकार, बच्चों को हमारी विकास कार्यसूची में प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता विद्यमान है। तथापि, ऐसी प्रतिबद्धताओं के परिणामों को अभी अमल में लाया जाना है। यहीं पर बालकों से संबंधित व्यापक सांख्यिकीय सूचना का व्यवस्थित संकलन करके हमारे बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के कार्य में लगे हुए हमारे नीति-निर्माताओं और योजनाकारों को दिशानिर्देशन प्रदान किया जा सकता है।

यह भी खुशी की बात है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने संस्थागत तंत्र के रूप में 'भारतीय बाल सांख्यिकीय मंच' को स्थापित करने पर अपनी सहमति दे दी है जिसमें

बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने वाले सभी प्रमुख हितार्थी शामिल होंगे। मैं इस मंच को स्थापित करने के लिए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि इससे हमारे बच्चों और उनके परिवारों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन एवं रिपोर्टिंग में समन्वय एवं सहयोग मिलेगा तथा उनकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता में सुधार आएगा। यह आबादी के सभी वर्गो में हमारे बच्चों की कुशलक्षेम से संबंधित राष्ट्रीय संकेतों का संकलन एवं उन पर नजर रखने तथा गैर- तकनीकी लोगों द्वारा समझे जाने वाले शब्दों के अनुसार आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को समर्थ बनाएगा।

देवियो और सज्जनो,

यद्यपि नीति-निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे सांख्यिकीविदों के योगदान को हमेशा सराहा है, तथापि प्रो. महालनोबिस और उनके जैसे अन्य महान सांख्यिकीविदों के समय से जनता में उनकी छवि में गिरावट आयी है। हमें हर संभव यह कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी तंत्र में हमारी सांख्यिकी वर्ग की कार्य-दशाओं और स्थितियों में सुधार आए। हमें युवाओं को शैक्षिक विषय और व्यवसाय के रूप में सांख्यिकी का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

मैं "सांख्यिकी दिवस-2010" के मौके पर आपके बीच परस्पर होने वाले वार्तालापों और विचार-विमर्शों में आपकी सफलता की कामना करता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि आप प्रोफेसर महालनोबिस की महान विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के लिए मुझे आमंत्रित किया।